(5) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

(6) सिंचाई क्षेत्र में संगठन और प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन ।

(7) सिंचाई प्रबन्ध नीति और

(8) राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय नदियों का जल आबंटन ।

सरकार की पूर्व व्यस्तता के कारण राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक सितम्बर, 1987 के बाद से नहीं हो सकी है ।

(ग) से (ङ) जी नहीं । सरकार सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से लम्बित अन्तर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत के जरिए हल करने के सभी प्रयास कर रही है । जब बातचीत से लाभदायक परिणाम नहीं निकलते हैं तो जल विवादों को संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत बनाये गये अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किए गए जल-विवाद अधिकरणों के पास अधिनिर्णय हेतु भेजे जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने अब ये पांच अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण नियुक्त किए हैं :

(1) गोदावरी जल-विवाद अधिकरण,

(2) कृष्णा विवाद अधिकरण,

(3) नर्मदा जल विवाद अधिकरण,

(4) रावी-व्यास जल अधिकरण, और

(5) कावेरी जल विवाद अधिकरण इनमें से चार अधिकरण नामश: कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और रावी-व्यास जल अधिकरण अपने-अपने निर्णय पहले ही दे चुके हैं ।

अन्य बातों के साथ-साथ परस्पर सहमत आधार पर अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के तरीकों पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1990 में सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थायी समिति का भी गठन किया गया ।

Central assistance for construction of check dams

5187. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat has sent any proposal for the Central assistance for the construction of check dams;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by the Central Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Check dams are generally constructed across gullies, nallas etc. in the catchment area of the rivers for soil and water conservation. Government of Gujarat has not sent any proposal exclusively for construction of check dams to the Central Government. Under the Centrally Sponsored Scheme of soil conservation in the catchments of river valley projects, an amount of Rs. 182.50 lakhs has been released by the Central Government to the Government of Gujarat during the year 1993-94 for soil & water conservation measures including check dams in the catchments of Dantiwada, Mahi, Ukai and Damanganga in Gujarat.

Special meeting of Chief Ministers to break the dead lock on SSP

5188. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Prime Minister had called a special meeting of Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh to break the deadlock on the Sardar Sarovar Project (SSP) on Narmada river;

(b) if so, whether the main points discussed in the meeting were rehabilitation of dam oustees as well as technical aspects of the project;

(c) if so, whether the Centre asked the States concerned to fully implement the